Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 10 | ISSUE : 6 | JUNE 2024

भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश की भूमिका

डॉ. सीताराम सिंह तोमर [1]

[1] **प्राचार्य, महाराजा मानसिंह महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.).**

ABSTRACT:

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में देशी संसाधनों एवं पूँजी के साथ-साथ विदेशी संसाधनों एवं पूँजी का भी महत्त्व होता है। अतः विश्व के अधिकांश देश एक-दूसरे के संसाधनों एवं पूँजी का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। भारत प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध देश है। यहाँ के उत्पादन विश्व प्रसिद्ध हैं। आज विश्व के प्रमुख देश भारत में अपनी पूँजी का निवेश कर रहे हैं। भारत में उदारीकरण एवं औद्योगीकरण के बाद पूँजी की आवश्यकता को विदेशी निवेश के द्वारा काफी हद तक आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी निवेश अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि इससे प्रौद्योगिकी के साथ-साथ अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है। वर्तमान में भारत एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में उभरा है। विदेशी निवेश पूँजी भारतीय कॉर्पोरेट की बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा को प्रदर्शित करता है। भारत में बढ़ता प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (थ्क्प्) स्पष्ट करता है कि जहाँ एक ओर भारत विश्व बाजार संभावना को ध्यान में रख रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय कम्पनियाँ विदेश में तेजी से अधिग्रहण करने में सफल रहीं हैं। वर्तमान में बेहतर आधारभूत संरचना एवं वित्तीय क्षेत्र में सुधारों से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (थ्क्प्) अन्तरप्रवाह में बढ़ोत्तरी हुई है।

KEYWORDS:

अर्थव्यवस्था, विदेशी निवेश, पूँजी, अधोसंरचना, उत्पादन एवं उत्पादकता.

PAPER ACCEPTED DATE:	PAPER PUBLISHED DATE:
28th June 2024	30th June 2024
IMPACT FACTOR VALUE:	**PAPER DOI LINK:**
5.983 (SJIF)	https://zenodo.org/records/14507549

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास स्थापित करने एवं संतुलन की स्थिति लाने के लिए सर्वप्रथम 6 अप्रैल 1949 को भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई। इस औद्योगिक नीति का प्रमुख उद्देश्य था कि देशी एवं विदेशी संस्थानों के बीच पूँजीगत भेदभाव नहीं किया जायेगा। विदेशी निवेशकों को आश्वासन दिया गया कि उनके लाभ एवं पूँजी को उन्हें अपने देश में ले जाने की उचित व्यवस्था की जायेगी। 1956 में नई औद्योगिक नीति का आर्थिक नियोजन में पंचवर्षीय विकास कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखकर घोषणा की गई। 1991 की औद्योगिक नीति में देश ने एक ऐसे स्वरूप को अपनाया जिससे विदेशी विनियोग एवं पूँजी को बढ़ावा देने के साथ–साथ विदेशियों को 51: पूँजी निवेश की छूट दी गई जो बाद में बढ़ाकर 78: तक कर दी गई।

अध्ययन के उद्देश्य

- विदेशी निवेश का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
- भारत में विदेशी निवेश हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।
- भारत में विदेशी निवेश का अध्ययन करना।
- विदेशी निवेश की समस्याओं का पता लगाना।
- विदेशी निवेश का मूल्यांकन करना।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध में वर्णनात्मक अध्ययन विधि का प्रयोग किया गया है जिसमें अध्ययन हेतु द्वितीयक समंकों का प्रयोग किया गया है।

भारत में विदेशी निवेश की आवश्यकता

भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अवस्था में है। भारत का प्रयास है कि हम विकसित अर्थव्यवस्था में पहुँच जायें किन्तु हम अभी भी अपने प्राकृतिक संसाधनों का समुचित एवं सही तरीके से दोहन नहीं कर पा रहे हैं। देश में पूँजी का अभाव है एवं लोगों में व्यावसायिक जोखिम उठाने की क्षमता कम है, साथ ही भारत में तकनीकी ज्ञान का स्तर भी पूर्णतया विकसित नहीं हो पाया है। नवीनतम प्रौद्योगिकी सहित पूँजीगत मशीनों का भी अभाव है। अतः हमें अपनी अर्थव्यस्था के विकास हेतु विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की आवश्यकता है जिसके अग्रलिखित कारण हैं –

- भारत में प्राकृतिक संसाधनों का भण्डार है अतः उनके उचित दोहन के लिए पूँजी की आवश्यकता है।
- विदेशी नवीन तकनीक का ज्ञान प्राप्त करने एवं उद्योगों को विकसित कर देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए।
- सार्वजनिक क्षेत्रों में गतिशीलता प्रदान करने एवं कुशलता को प्रोत्साहित करने के लिए।
- अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश कर प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए।
- देश में उद्योगों के नवाचार एवं बेरोजगारी दूर करने के लिए।
- विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बेहतर तालमेल करने के लिए एवं मूलभूत समस्याओं के निराकरण के लिए।
- वित्तीय क्षेत्र में आधारभूत सुधारों के जरिए बेहतर पूँजी एवं मुद्रा बाजार को विकसित करने के लिए।

भारत में विदेशी निवेश के घटक

भारत में विदेशी निवेश के दो घटक हैं –

- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (थ्वतमपहद क्पतमबज प्दअमेजउमदज) : विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (थ्क्प्) से आशय है कि कोई विदेशी नागरिक अथवा संगठन दूसरे देश में अपनी पूँजी द्वारा उत्पादन इकाई की

स्थापना करता है। ऐसे निवेश पर निवेशक का स्वामित्व प्रबंध में नियंत्रण रहता है। भारत में यह निवेश भारतीय रिजर्व बैंक औद्योगिक सहायता सचिवालय एवं विदेशी विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड के द्वारा होता है।

- पोर्टफोलियो निवेश (च्वतजविसपव प्दअमेजउमदज) : इसके अन्तर्गत विदेशी कम्पनियाँ भारतीय कम्पनियों के ऋण पत्र या अंश खरीद कर निवेश करती हैं। इस प्रकार के निवेश में विदेशी कम्पनियों का स्वामित्व, प्रबंधन एवं नियंत्रण न होकर केवल लाभांश एवं ब्याज प्राप्त करने तक सीमित रहता है। भारत के संदर्भ में पोर्टफोलियो निवेश का आशय विदेशी संस्थागत निवेश या भूमण्डलीय न्यासी रसीद या अमरीकी न्यासी रसीद या अपटीप फण्ड या अन्य द्वारा घरेलू पूँजी बाजार में प्रतिभूतियों में विनियोग से है।

भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की स्थिति

स्वतंत्रता के बाद देश में आर्थिक सुधारों के बाद से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (थ्क्) की स्थिति में लगातार सुधार हुआ। वर्ष 1990–91 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मात्र 165 मिलियन अमरीकी डॉलर था जो 1998–99 तक 3682 मिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच गया। यह हमारी सूझ–बूझ एवं आर्थिक उदारीकरण का परिणाम ही था। वैश्विक मंदी के कारण 2001–02 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में लगातार कमी होती गई किन्तु 2004–05 में पुनः बढ़कर यह 3754 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। 2014 में यह निवेश बढ़कर 721 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। 2017 एवं 2018 में क्रमशः इसमें 46: एवं 54: की अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई।

सारणी क्रमांक– 1

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

भारत में संचयी प्रवाह में हिस्सेदारी

(2015–2019)

देश	संचयी अंतर्वाह (:)
सिंगापुर	27.7
मॉरीशस	27.0
अमेरिका	7.5
नीदरलैंड	7.5
जापान	7.0
कुल	76.7

स्रोतः आरबीआई वार्शिक रिपोर्ट (2018–19) में केवल एसआईए/एफआईपीबी और आरबीआई मार्गों के माध्यम से एफडीआई भाामिल है।

2015 से 2019 के दौरान, भारत को 173.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संचयी एफडीआई अंतर्वाह प्राप्त हुआ और भारत में शीर्ष पांच निवेश करने वाले देशों की हिस्सेदारी 76.7 प्रतिशत रही। सिंगापुर और मॉरीशस ने मिलकर भारत में कुल विदेशी निवेश का आधे से अधिक हिस्सा हासिल किया, जिसमें कुल संचयी एफडीआई अंतर्वाह में 27.7 प्रतिशत का उच्चतम हिस्सा सिंगापुर का था। 2015–2019 के दौरान तीन प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् 'विनिर्माण क्षेत्र', 'संचार सेवा' और 'वित्तीय सेवा'' ने समग्र रूप से 89.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एफडीआई अंतर्वाह में 50 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी प्राप्त की।

सारणी क्रमांक– 2

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

कंपनियों की क्षेत्रवार इक्विटी भागीदारी : मार्च 2019

क्र.	गतिविधि	कुल इक्विटी (निवासी और अनिवासी सहित)	एफडीआई इक्विटी हिस्सेदारी अंकित मूल्यों पर	बाजार मूल्य पर
1	कृषि से संबंधित, वृक्षारोपण और संबद्ध गतिविधियाँ	1,838	1,698	7,060
2	खनन	1,657	1,390	6,456
3	निर्माण	3,21,314	2,81,560	16,64,304
4	बिजली, गैस, भाप और एयर कंडीशनिंग आपूर्ति	47,545	27,136	59,016
5	जल आपूर्ति, सीवरेज, अपशिष्ट प्रबंधन और उपचारात्मक गतिविधियाँ	1,996	1,792	2,745
6	निर्माण	25,160	19,647	41,009
7	सूचना और संचार	58,874	45,448	5,41,385
8	अन्य सेवाएं	2,92,143	2,30,651	7,99,410
	कुल	**7,50,527**	**6,09,322**	**31,21,385**

स्रोत : आरबीआई डेटा विज्ञप्ति – भारत की विदेशी देयताओं और आस्तियों की वार्शिक जनगणना (2020)।

सारणी क्रमांक– 3

इक्विटी अनुपात (अंकित मूल्य से बाजार मूल्य)

सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि : क्षेत्र–वार

क्र.	गतिविधि	बाजार मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात	औसत वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि (2000–2019)
1	कृषि से संबंधित, वृक्षारोपण और संबद्ध गतिविधियाँ	4.2	3.2
2	खनन	4.6	4.2
3	निर्माण	5.9	7.5
4	बिजली, गैस और पानी की आपूर्ति	3.7	6.6
5	निर्माण	2.1	6.6
6	सूचना और संचार	11.9	18.3
7	अन्य सेवाएं	3.5	8.3
	कुल	**5.1**	**7.0**

स्रोत : आरबीआई डेटा विज्ञप्ति (2020) और सीएसओ डेटा।

सारणी क्रमांक– 4

बाजार मूल्य और कुल निर्यात पर कुल

एफडीआई का गतिविधिवार हिस्सा : 2018–19

क्र.	गतिविधि	बाजार मूल्य पर कुल एफडीआई का हिस्सा (प्रतिशत)	कुल निर्यात का हिस्सा (प्रतिशत)

1	सूचना और संचार	16.7	45.5
2	वित्तीय और बीमा गतिविधियाँ	14.0	1.4
3	मोटर वाहन, ट्रेलर और अर्ध–ट्रेलर	6.9	7.2
4	अन्य सेवा गतिविधियाँ	5.2	10.7
5	खाद्य उत्पाद	4.7	0.8
6	रसायन और रासायनिक उत्पाद	4.0	1.6
7	मशीनरी और उपकरण एनईसी	3.6	3.4
8	फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय और रासायनिक उत्पाद	3.5	3.0
9	थोक और खुदरा व्यापार, मोटर वाहनों और मोटरसाइकिलों की मरम्मत	3.2	7.6
10	अन्य	38.2	18.8
	कुल	**100.0**	**100.0**

स्रोत : आरबीआई डेटा विज्ञप्ति – भारत की विदेशी देयताओं और आस्तियों की वार्शिक जनगणना (2020)।

चूंकि सीडीआईएस में भाग लेने वाले सभी देश भागीदार देशवार प्रत्यक्ष निवेश (अंतर्वाही या बहिर्गामी या दोनों) की रिपोर्ट करते हैं, इसिलए शीर्ष नौ स्रोत देशों से, जो मार्च 2019 में एफएलए जनगणना परिणामों के अनुसार भारत में समग्र रूप से एफडीआई स्टॉक का 78.9 प्रतिशत हिस्सा है, अंतर्वाही प्रत्यक्ष निवेश की स्टॉक स्थिति को सत्यापित करने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। मार्च 2019 में कुल एफडीआई स्टॉक में यूएसए की सबसे बड़ी हिस्सेदारी (17.8 प्रतिशत) थी। यह उल्लेखनीय है कि निवेश और निवेशित देशों द्वारा रिपोर्ट किए गए एफडीआई का स्टॉक विभिन्न कारणों से कई मामलों में भिन्न होता है और इसे केवल संदर्भ तिथि में केवल 3 महीने के अंतर के लिये जोड़ा नहीं जा सकता है। यह अंतर शामिल किए गए निवेशक/निवेशित फर्मों के आकलन पद्धति (जनगणना बनाम सर्वेक्षण), लेखांकन आर मूल्यांकन की कठिनाइयों, रिपोर्टिंग त्रुटियों आदि के कारण भी हो सकता है।

सारणी क्रमांक– 5

बाजार मूल्य पर स्रोत देश–वार एफडीआई

देश	भारत में एफडीआई (रू. करोड़)	
	एफएलए जनगणना परिणामों के अनुसार (मार्च'19)	सीडीआईएस में भागीदार दे□ा द्वारा रिपोर्ट किया गया (दिसम्बर'18)
अमेरिका	5,84,978	3,20,933
यूनाइटेड किंगडम	5,17,369	1,28,814
मॉरीशस	5,09,914	8,79,038
जापान	2,82,724	1,69,877
नीदरलैंड	2,50,491	1,76,888
जर्मनी	1,63,773	1,95,789
स्विट्जरलैंड	1,59,576	44,273
कोरिया गणराज्य	79,578	42,646
फ्रांस	48,135	44,199
उपरोक्त सभी देश	25,96,538	20,02,456
सिंगापुर	4,13,174	Not Reported
अन्य देश	2,83,190	All Not Reported
सभी देश	32,92,902	All Not Reported

स्रोत : आरबीआई डेटा रिलीज (2020) और आईएमएफ की वेबसाइट http://cdis.imf.org

एफडीआई अंतर्वाह को प्रभावित करने वाले कारकों का अनुभवजन्य विश्लेशण

इस खंड में, हर प्रमुख साझेदार देशों में एफडीआई अंतर्वाह को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को निर्धारित करने के लिए भारत में एफडीआई स्टॉक का पर्याप्त हिस्सा रखने वाले एक पैनल के अभ्यास के परिणाम को प्रस्तुत कर रहे हैं। इस आंकड़ा समूह में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं जैसे यूएसए, यूके, मॉरीशस, जापान, नीदरलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, कोरिया, गणराज्य, फ्रांस और भारत के लिए 2009–10 से 2017–18 की अवधि के अवलोकन शामिल हैं। संपूर्ण आंकड़ा समूह विश्व बैंक, आईएमएफ, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) तथा विश्व बैंक डेटाबेस द्वारा प्रकाशित वैश्विक विकास वित्त से प्राप्त किया गया है।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की समस्याएँ

भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश के कारण अनेक आशंकाएँ एवं समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, इनमें प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं।

- कोई भी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश केवल सम परिस्थितियों में ही किया जाता है और विषय परिस्थितियों को झेलने के लिए तैयार नहीं होता।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होने के कारण घरेलू स्वदेशी उद्योग आज अपनी कुशलता एवं गुणवत्ता विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण खोते जा रहे हैं।
- समय–समय पर सरकारों के परिवर्तित होने से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की विश्वसनीयता में कमी आ जाती है।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश विकासोन्मुखी होते हुए भी गरीबी एवं बेरोजगारी जैसी प्रमुख समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ रहा है।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सभी क्षेत्रों में विस्तृत न होकर केवल लाभप्रद क्षेत्रों तक ही सीमित हो गया है।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होने से अर्थव्यवस्था में आय की असमानताओं की समस्या बढ़ी है।
- कभी–कभी सरकार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर इतनी छूट प्रदान कर देती है कि प्रत्यक्ष निवेश के बहाने विदेशी गुप्तचर एजेन्सियाँ भी अपनी मुद्रा भेज देती हैं, जो देश में समस्या उत्पन्न कर देती हैं।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित दोहन की सम्भावना रहती है।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश देश के श्रम कानूनों को अनावश्यक रूप से प्रभावित करता है।
- कभी–कभी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ऐसी कठिन शर्तों के साथ किया जाता है, जिससे कि बाद में हानि होती है।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के प्रति निष्ठावान नहीं हैं।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कारण लाभों के रूप में भारतीय संसाधन विदेशों में चले जाते हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को हानि होती है।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु सुझाव

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित करने के सम्बंध में प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हो सकते हैं –

- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों, निर्यातोन्मुखी उद्योगों तथा पर्यटन क्षेत्रों में यह पूँजी लगाई जा सके।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में लगी पूँजी तथा उससे उत्पन्न होने वाली आय की वापसी के बारे में कानूनी स्थिति स्पष्ट की जाए।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के विषय में कानूनों का सरलीकरण किया जाए।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर करों में छूट प्रदान की जाए।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से यदि देश के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो, तो ऐसे मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप न किया जाए।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को उपभोक्ता उद्योगों में अपनी सहभागिता बढ़ाने का मौका दिया जाना चाहिए।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकारी प्रशासन का पुनर्गठन किया जाए और अनुत्पादक एवं सार्वजनिक खर्च में कमी लाकर वित्तीय घाटे में कमी लाई जाए।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कर्मचारियों को पूर्णतया प्रशिक्षित कर उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय एवं उदारीकृत आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप उनकी दक्षता में वृद्धि की जाए।
- सरकार द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हेतु स्थायी एवं व्यापक रूप से नीति तैयार की जाए।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेशकर्ताओं को आकर्षित करने हेतु विस्तृत एवं व्यापक स्तर पर बाजार उपलब्ध कराया जाए।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रोत्साहन हेतु देश में प्रभावी एवं स्थायी सरकार का गठन किया जाए।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहन हेतु निवेशकर्ताओं को विपणन गतिविधियों एवं निर्णयन में स्वतंत्रता एवं छूट प्रदान की जाए।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु निवेशकर्ताओं की गतिविधियों पर ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक निवेश करने की छूट प्रदान की जाए एवं प्रबन्ध में उनकी ओर अधिक हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अन्तर्गत उन्नत तकनीकी का प्रयोग विकास की प्रारम्भिक अवस्था में तथा उद्योगों की नई इकाइयों को स्थापित करने में किया जाए।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बेहतरी के लिए देश में केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल रखा जाए कि जिस राज्य में यह निवेश होना है उसके वरिष्ठ अधिकारी भी निर्णय के समय उपस्थित रहें।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के सन्दर्भ में निजीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाए और निवेशकों के अनुरूप ही नीतियाँ बनाई जाए।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के सन्दर्भ में यदि कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाए, तो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

निष्कर्ष

भारतीय अर्थव्यवस्था के उत्थान में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। देश के प्रमुख भारी उद्योगों के निर्माण एवं विकास में इसके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है, किन्तु विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं सहयोग के पूर्णतया राजनीतिक सम्बन्धों पर आधारित होने के कारण देश में सदैव अनिश्चितता का वातावरण बना रहता है। इन अनिश्चितताओं के कारण योजनाओं का निरूपण नहीं हो पाता। हमारे देश में चिन्ता का विषय, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में कमी होना नहीं है, बल्कि योजनाओं का कुशल आकलन एवं संचालन की भारी कमी है जिसके परिणामस्वरूप विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अपनी भरपूर क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाता। जब तक भारतीय अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर नहीं हो पाती तब तक इस तरह के पराश्रय एवं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की आवश्यकता देश को परेशान किए रहेगी। अतः विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के लिए हमें अपने घरेलू बाजार, सस्ते एवं प्रशिक्षित कामगारों, तकनीकी विशेषज्ञों की अधिकता आदि सकारात्मक पहलुओं का लाभ उठाना चाहिए और अपनी अर्थव्यवस्था में किए जा रहे वित्तीय एवं आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को और अधिक तेजी से तथा दीर्घकाल तक जारी रखा जाना चाहिए तभी हम अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में कामयाब हो सकेंगें।

REFERENCES

1. भारत में आर्थिक पर्यावरण–डॉ.पी.डी. महेष्वरी, डॉ.षीलचंद्र गुप्ता (2014)।
2. भारतीय अर्थव्यवस्था एवं विदेषी निवेष, पी.के. चट्टोपाध्याय (2012)।
3. इकोनोमिक्स सॉवेनियर, मिनिस्ट्री ऑफ फायनेंस, भारत सरकार (2015)।
4. भारत (2011), प्रकाषन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
5. मध्यप्रदेष सम्पूर्ण अध्ययन, उपकार प्रकाषन आगरा, षादाब अहमद सिद्दीकी (2014)।
6. सामान्य अध्ययन, पियर्सन एजूकेषन, नई दिल्ली (2009) एडगर थोर्प, षोवेक थोर्प।
7. प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक (2021)।
8. कुरूक्षेत्र सितम्बर दिल्ली (2018)।
9. आर्थिक समीक्षा, 2020–2021.